



*The*  
**ACHIEVERS**  
IAS ACADEMY  
PATNA

*Daily*  
**NEWS CHRONICLE**

**IDEAL FOR**

For UPSC/BPSC & For other Exams

**Hindi**

**NEWS CREDIT**

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

**NEWS COVERED**

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...



**Tuesday, August 04, 2026**



+91 8434931877



[www.achieversiaspatna.co.in](http://www.achieversiaspatna.co.in)



[achieversiaspatna@gmail.com](mailto:achieversiaspatna@gmail.com)

## दिन की प्रमुख घटनाएं

- भारत ने देश भर में रणनीतिक संपर्क को मजबूत करने के लिए **45,000 करोड़ रुपये** की सीमा रेलवे विस्तार की योजना बनाई है।
- पीएम मोदी ने युवाओं के बीच नशे के दुरुपयोग के खिलाफ **नशा मुक्त युवा** अभियान की शुरुआत की।
- मंत्रिमंडल ने 36,441 करोड़ रुपये के खेल विकास परियोजना के साथ **विस्तारित खेलो इंडिया योजना** को मंजूरी दी।
- भारत और मालदीव ने सीमा पार से धन हस्तांतरण के लिए फवरा-यूपीआई कॉरिडोर का शुभारंभ किया।
- **वर्षा अशोक अगावे** जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक बनीं।
- **विली वॉल्श** ने आधिकारिक तौर पर पीटर एल्बर्स की जगह लेते हुए इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला।
- जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका बाजारों को स्थिर करने के लिए **दुर्लभ संयुक्त येन-खरीद** हस्तक्षेप करते हैं।
- सरकार ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देने के लिए **बैंकर्स बुक एक्टिविटी बिल, 2026** पेश किया।
- रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने **बॉन ओपन टेनिस टूर्नामेंट** का डबल्स खिताब जीता।
- रक्षा मंत्रालय ने **भारतीय नौसेना के पानी के भीतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी डीएससी ए24** लॉन्च किया।



## भारत ने सीमा संपर्क को मजबूत करने के लिए 45,000 करोड़ रुपये के रेलवे विस्तार की योजना बनाई है



यह खबरों में क्यों है?

- भारत सरकार चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ देश की सीमाओं पर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 45,000 करोड़ रुपये के रेलवे बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की योजना बना रही है। प्रस्तावित परियोजनाओं का उद्देश्य रणनीतिक गतिशीलता को मजबूत करना, सीमा सुरक्षा बढ़ाना, नागरिक संपर्क में सुधार करना और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और उपकरणों की तेजी से आवाजाही का समर्थन करना है।

मुख्य बिंदु

- भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में रेलवे परियोजनाओं में लगभग 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है।
- यह पहल चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं के पास रेल संपर्क में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- सीमावर्ती राज्यों में कई नई रेल लाइनें और रणनीतिक रेल लिंक प्रस्तावित हैं।
- इन परियोजनाओं का उद्देश्य आपात स्थिति के दौरान सैनिकों, सैन्य उपकरणों और आवश्यक आपूर्ति की तेजी से तैनाती को सक्षम करना है।

पृष्ठभूमि

- बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और तेजी से सैन्य तैनाती की आवश्यकता के बाद भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। जबकि हाल के वर्षों में सड़कों और पुलों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है, रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कुशल रसद और सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है।

महत्व

- प्रस्तावित रेलवे विस्तार से सैनिकों को तेजी से जुटाने और बेहतर रसद को सक्षम करके राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार होगा। यह क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा, दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार करेगा और

उभरती सुरक्षा चुनौतियों के खिलाफ भारत के सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।

परीक्षा फोकस पॉइंट

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • परियोजना: रणनीतिक सीमा रेलवे विस्तार कार्यक्रम।                                                |
| • प्रस्तावित निवेश: ₹45,000 करोड़                                                                |
| • कवर किए गए सीमावर्ती देश: चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश।                                        |
| • उद्देश्य: सीमा संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक रसद को मजबूत करना।                         |
| • प्रमुख लाभ: तेज सैन्य आवाजाही, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला, क्षेत्रीय विकास और बेहतर नागरिक संपर्क। |
| • कार्यान्वयन एजेंसी: रेल मंत्रालय (सरकारी अनुमोदन के अधीन)।                                     |

राजनीतिक और सर्वोच्च नेतृत्व

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| • सुप्रीम कमांडर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (भारत के राष्ट्रपति) |
| • रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह                                      |
| • रक्षा सचिव: राजेश कुमार सिंह                                   |

सेवा प्रमुख और सैन्य कमान

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| • चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस): जनरल एनएस राजा सुब्रमणि (31 मई, 2026 से)       |
| • थल सेनाध्यक्ष (COAS): जनरल धीरज सेठ (30 जून, 2026 से)                        |
| • नौसेना प्रमुख (CNS): एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन (1 जून, 2026 से)               |
| • वायु सेना प्रमुख (सीएएस): एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह (30 सितंबर, 2024 से) |

आगे की राह

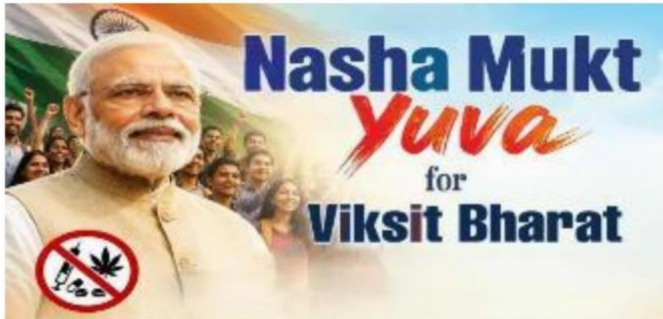
- रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सीमा बुनियादी ढांचा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ-साथ प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं का समय पर निष्पादन आवश्यक होगा। रेल, सड़क और हवाई संपर्क को एकीकृत करने से भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूती मिलेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम मोदी ने युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए 'नशा मुक्त युवा' अभियान शुरू किया

यह खबरों में क्यों है?



- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी 'नशा मुक्त युवा' अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, नशीली दवाओं से मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना और नशीली दवाओं की लत को रोकने में शैक्षणिक संस्थानों, समुदायों और सरकारी एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।



मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नशा मुक्त युवा' अभियान की शुरुआत की।
- इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन और नशीली दवाओं की लत को रोकना है।
- यह जागरूकता, रोकथाम, परामर्श, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है।
- अभियान में स्कूल, कॉलेज, युवा संगठन, गैर सरकारी संगठन और सरकारी विभाग भाग लेंगे।
- यह पहल युवा लोगों के बीच एक स्वस्थ, नशीली दवाओं से मुक्त और जिम्मेदार जीवन शैली को बढ़ावा देती है।
- यह सरकार के व्यापक नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) का पूरक है।

#### व्हाट इज नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)?

- लॉन्च: 15 अगस्त 2020।
- नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
- उद्देश्य: जागरूकता, परामर्श, उपचार, पुनर्वास और सामुदायिक आउटरीच के माध्यम से नशीली दवाओं की मांग को कम करना।
- यह अभियान शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवकों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पूरे भारत के संवेदनशील जिलों में लागू किया गया है।

#### महत्व

- अभियान का उद्देश्य युवा लोगों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को कम करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, सामाजिक जागरूकता को मजबूत करना और देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की रक्षा करना है। यह नशा मुक्त समाज बनाने में सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।

#### परीक्षा फोकस पॉइंट

- अभियान: नशा मुक्त युवा अभियान।
- द्वारा लॉन्च किया गया: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी।
- उद्देश्य: युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन को रोकना।
- लक्ष्य समूह: युवा और छात्र।
- फोकस क्षेत्र: जागरूकता, रोकथाम, परामर्श, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी।
- रिलेटेड इनिशिएटिव: नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)।
- एनएमबीए लॉन्च: 15 अगस्त 2020।
- नोडल मंत्रालय (एनएमबीए): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

#### भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मादक द्रव्यों की लत के खिलाफ सरकार की प्रमुख पहल

- पहल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया वस्तुनिष्ठ
- नशा मुक्त युवा अभियान (2026) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागरूकता, परामर्श, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को रोकना।
- नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) (2020) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामुदायिक आउटरीच के माध्यम से नशीली दवाओं की मांग को कम करना।
- मानस राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14446/1-800-891-4416) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं की लत मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए परामर्श और रेफरल सेवाएं प्रदान करता है।
- नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) (2018-25) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय निवारक शिक्षा, जागरूकता, उपचार, पुनर्वास, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष (एनएफसीडीए) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी और पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- नशा मुक्त भारत पखवाड़ा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ स्कूलों, कॉलेजों, एनएसएस, एनवाईकेएस और स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान।
- एनसीबी द्वारा नशीली दवाओं से मुक्त भारत अभियान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए



|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>जागरूकता अभियान, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान और सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है।</p>                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                     प्रोजेक्ट सनराइज (2016) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका उद्देश्य विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में ड्रग्स इंजेक्ट करने वाले लोगों के बीच एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकना है।                 </li> </ul> |

**केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 36,441 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी**



यह खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपये के संयुक्त परिव्यय के साथ एक विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को बढ़ी हुई सहायता को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य जमीनी स्तर के खेलों को मजबूत करना, युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एथलीटों को तैयार करना है।

मुख्य बिंदु

|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             कुल परिव्यय: 2026-27 से 2030-31 के लिए ₹36,441 करोड़।                         </li> </ul>                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को सहायता को शामिल करता है।                         </li> </ul>                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान, एथलीट विकास, कोचिंग और खेल के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करें।                         </li> </ul>             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             इसका उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक एथलीटों के लिए एक स्पष्ट मार्ग बनाना है।                         </li> </ul> |

**खेलो इंडिया के बारे में**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             लॉन्च किया गया: 2017-18।                         </li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय।                         </li> </ul>                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             उद्देश्य: खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन में सुधार करना।                         </li> </ul> |

- प्रमुख आयोजनों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, बीच गेम्स और ट्राइबल गेम्स शामिल हैं।

**राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) क्या हैं?**

- राष्ट्रीय खेल महासंघ युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त खेल-विशिष्ट शासी निकाय हैं। वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन, भारतीय टीमों का चयन करने, एथलीटों को प्रशिक्षण देने और अपने संबंधित खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं।

- विस्तारित योजना बुनियादी ढांचे, कोचिंग, एथलीट सहायता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार करके भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी। यह एक अग्रणी खेल राष्ट्र के रूप में उभरने और वैश्विक आयोजनों में बेहतर प्रदर्शन करने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप भी है।

**परीक्षा फोकस पॉइंट**

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             योजना: खेलो इंडिया योजना।                         </li> </ul>                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             द्वारा स्वीकृत: केंद्रीय मंत्रिमंडल।                         </li> </ul>                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             कुल परिश्रम: ₹36,441 करोड़                         </li> </ul>                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             कार्यान्वयन अवधि: 2026-27 से 2030-31।                         </li> </ul>                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय।                         </li> </ul>                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             लॉन्च किया गया: 2017-18।                         </li> </ul>                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             फोकस: जमीनी स्तर के खेल, एथलीट विकास, खेल बुनियादी ढांचा और एनएसएफ को समर्थन।                         </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>                             संबंधित योजना: राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को सहायता।                         </li> </ul>                        |

**भारत और मालदीव ने तत्काल सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए फवरा-यूपीआई भुगतान कॉरिडोर का शुभारंभ किया**



### यह खबरों में क्यों है?

- भारत और मालदीव ने फवरा-यूपीआई क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर लॉन्च किया है, जो मालदीव से भारत में यूपीआई-सक्षम बैंक खातों में वास्तविक समय में धन हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। यह पहल डिजिटल वित्तीय कनेक्टिविटी को मजबूत करती है और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करती है।

### मुख्य बिंदु

- मालदीव की तत्काल भुगतान प्रणाली, फवरा को भारत के यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के साथ एकीकृत किया गया है।
- मालदीव में लोग अब मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से भारत में यूपीआई से जुड़े बैंक खातों में तुरंत पैसे भेज सकते हैं।
- यह सेवा मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA) द्वारा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के साथ साझेदारी में शुरू की गई है।
- बैंक ऑफ मालदीव और मालदीव इस्लामिक बैंक पहले भाग लेने वाले बैंक हैं।
- भविष्य के चरणों में क्यूआर-कोड व्यापारी भुगतान और अतिरिक्त सीमा पार भुगतान सेवाएं शामिल होंगी।

### यूपीआई क्या है?

- यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक वास्तविक समय डिजिटल भुगतान प्रणाली है। यह मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके तत्काल बैंक-टू-बैंक हस्तांतरण को सक्षम बनाता है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित है।

**वर्षा अशोक अग्रवाल जीएसआई के 176 साल के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक बनीं**



### फवरा क्या है?

- फवरा मालदीव की तत्काल भुगतान प्रणाली है, जिसे देश के भीतर सुरक्षित और वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है।

### महत्व

- फवरा-यूपीआई कॉरिडोर प्रेषण को तेज, सस्ता और अधिक सुरक्षित बनाएगा। यह भारत-मालदीव आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है, पर्यटन और व्यापार का समर्थन करता है और भारत के यूपीआई इकोसिस्टम के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करता है।

### परीक्षा फोकस पॉइंट

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • पहल: फवरा-यूपीआई क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर।                                                         |
| • देश: भारत और मालदीव।                                                                                  |
| • भारत की भुगतान प्रणाली: यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई)।                                           |
| • मालदीव की भुगतान प्रणाली: फवरा।                                                                       |
| • भारतीय भागीदार: NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL)।                                               |
| • मालदीव पार्टनर: मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA)।                                                       |
| • पहले भाग लेने वाले बैंक: बैंक ऑफ मालदीव और मालदीव इस्लामिक बैंक।                                      |
| • उद्देश्य: वास्तविक समय में सीमा पार फंड ट्रांसफर को सक्षम करना और डिजिटल वित्तीय सहयोग को मजबूत करना। |

### आगे की राह

- मर्चेट भुगतान, अतिरिक्त बैंकों और अधिक सीमा पार वित्तीय सेवाओं को शामिल करने के लिए फवरा-यूपीआई कॉरिडोर का विस्तार करने से क्षेत्रीय डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह पहल भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

### यह खबरों में क्यों है?

- वर्षा अशोक अगावे अपने 176 साल के इतिहास में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की पहली महिला महानिदेशक (डीजी) बन गई हैं। उनकी नियुक्ति भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और देश के वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में नेतृत्व के पदों पर महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

### मुख्य बिंदु



- वर्षा अशोक अगावे को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- वह 1851 में संगठन की स्थापना के बाद से इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं।
- जीएसआई भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज अन्वेषण और भूवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत की प्रमुख एजेंसी है।
- उनकी नियुक्ति से वैज्ञानिक अनुसंधान, खनिज संसाधन अन्वेषण और भूवैज्ञानिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को मजबूत करने की उम्मीद है।

### भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के बारे में

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक है, जिसे 1851 में स्थापित किया गया था। यह खान मंत्रालय के तहत कार्य करता है और भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज अन्वेषण, भूवैज्ञानिक अध्ययन, प्राकृतिक खतरे के आकलन और पर्यावरण भूविज्ञान के लिए जिम्मेदार है। जीएसआई खनिज नीति, बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक इनपुट भी प्रदान करता है।

### महत्व

- वर्षा अशोक अग्रवाल की नियुक्ति भारत के वैज्ञानिक संस्थानों में लैंगिक प्रतिनिधित्व के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे खनिज अन्वेषण, संसाधन प्रबंधन और सतत विकास में देश के प्रयासों को मजबूत करते हुए भूविज्ञान में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रेरित करने की उम्मीद है।

### विली वॉल्श ने इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला



- वयोवृद्ध वैश्विक विमानन कार्यकारी विली (विलियम) वाल्श ने आधिकारिक तौर पर इंडिगो (इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो पीटर एल्बर्स के स्थान पर है।
- वॉल्श इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के महानिदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद एयरलाइन में शामिल हुए।
- पूर्व नेतृत्व भूमिकाएँ: ब्रिटिश एयरवेज, एयर लिंगस और इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप (IAG) के सीईओ।
- फोकस क्षेत्र: वैश्विक विस्तार, परिचालन उत्कृष्टता, नेटवर्क विकास और ग्राहक अनुभव।

### परीक्षा फोकस पॉइंट

- पर्सन: वर्षा अशोक अगलावे।
- नियुक्ति: महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)।
- उपलब्धि: जीएसआई के 176 साल के इतिहास में पहली महिला डीजी।
- संगठन: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)।
- स्थापित: 1851।
- मंत्रालय: खान मंत्रालय।
- मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
- कार्य: भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज अन्वेषण, भूवैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक खतरे का आकलन और पर्यावरण भूविज्ञान।

### आगे की राह

- अनुसंधान को मजबूत करना, उन्नत भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना, टिकाऊ खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देना और भूविज्ञान में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना भारत के आर्थिक विकास और संसाधन सुरक्षा में जीएसआई के योगदान को और बढ़ाएगा।

### इंडिगो के बारे में

- इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड द्वारा संचालित इंडिगो, बाजार हिस्सेदारी और यात्री यातायात के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है।
- मूल कंपनी: इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड
- स्थापित: 2006
- मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा

### IATA के बारे में:

- इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) एयरलाइन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक व्यापार संघ है।
- स्थापित: 1945
- मुख्यालय: मॉन्ट्रियल (कनाडा) और जिनेवा (स्विट्जरलैंड)

### इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप (IAG) के बारे में:

- इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप (आईएजी) दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन होल्डिंग कंपनियों में से एक है।

|                                    |
|------------------------------------|
| • जेवियर फेरन (अध्यक्ष)            |
| • लुइस गैलेगो (सीईओ)               |
| • स्थापित: 2011                    |
| • पंजीकृत कार्यालय: मैड्रिड, स्पेन |
| • आईएजी के तहत प्रमुख एयरलाइंस     |
| • ब्रिटिश एयरवेज।                  |
| • इबेरिया।                         |
| • एर लिंगस।                        |
| • वुएलिंग।                         |
| • स्तर।                            |

#### प्रमुख सरकारी पहल

|                                                |
|------------------------------------------------|
| • उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)                |
| • 2016 में लॉन्च किया गया।                     |
| • क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाता है।          |
| • हवाई यात्रा को किफायती बनाता है।             |
| • राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी), 2016 |

#### नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA):

|                              |
|------------------------------|
| • मुख्यालय: नई दिल्ली        |
| • महानिदेशक: वीर विक्रम यादव |

#### भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई):

|                        |
|------------------------|
| • स्थापित: 1995        |
| • अध्यक्ष: विपिन कुमार |
| • मुख्यालय: नई दिल्ली  |

#### अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)

|                                        |
|----------------------------------------|
| • स्थापित: 1944 (शिकागो कन्वेंशन)      |
| • मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा          |
| • महासचिव: जुआन कार्लोस सालाजार गोमेज़ |
| • परिषद अध्यक्ष: तोशीयुकी ओनुमा        |

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| • इंडिगो के नए सीईओ: विली (विलियम) वॉल्श।                              |
| • सफल: पीटर एल्बर्सी                                                   |
| • पूर्व पद: आईएटीए के महानिदेशक।                                       |
| • पूर्व सीईओ: ब्रिटिश एयरवेज, एयर लिंगस और आईएजी।                      |
| • एयरलाइन: इंडिगो (इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड)।                          |
| • इंडिगो का मुख्यालय: गुरुग्राम।                                       |
| • वैश्विक विमानन निकाय: आईएटीए।                                        |
| • भारत में नागरिक उड्डयन नियामक: डीजीसीए।                              |
| • एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)। |
| • संबंधित नीति: राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016                     |

### जापान और अमेरिका ने दुर्लभ संयुक्त येन-खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की



- जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी येन का समर्थन करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में एक दुर्लभ समन्वित हस्तक्षेप की पुष्टि की है, जो

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 40 वर्षों में अपने सबसे कमजोर स्तर पर गिर गया था।

- दोनों देशों ने संयुक्त रूप से येन खरीदा और अत्यधिक अस्थिरता को रोकने और वित्तीय बाजारों को स्थिर करने के लिए अमेरिकी डॉलर बेचे।
- जापान ने यह भी संकेत दिया कि वह विनिमय दर में अव्यवस्थित गतिविधियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो, तो और समन्वित हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है।
- यह 2011 के बाद से पहला संयुक्त येन-खरीद हस्तक्षेप है।

#### हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों थी?



- जापानी येन निम्न कारणों से काफी कमजोर हो गया है:
- संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच बढ़े ब्याज दर का अंतर।
- उच्च अमेरिकी ब्याज दरें वैश्विक पूंजी को आकर्षित करती हैं।
- जापान की लंबे समय तक उदार मौद्रिक नीति।
- बढ़ती आयात लागत, विशेष रूप से ईंधन और भोजन के लिए।
- जापान में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया।

- समन्वित हस्तक्षेप का उद्देश्य मुद्रा में विश्वास बहाल करना और अव्यवस्थित बाजार आंदोलनों को रोकना था।

मुद्रा बाजार हस्तक्षेप क्या है?

- मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किसी देश के केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा विदेशी मुद्राओं को खरीदने या बेचने के लिए अपनी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने की कार्रवाई है।

हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

- वैश्विक वित्तीय बाजारों में स्थिरता का समर्थन करता है।
- कमजोर मुद्रा से जापान की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करता है।
- आयातित मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है।
- जापान और अमेरिका के बीच घनिष्ठ आर्थिक समन्वय का संकेत।
- भविष्य के बैंक ऑफ जापान (बीओजे) मौद्रिक नीति के बारे में अपेक्षाओं को प्रभावित कर सकता है।

बैंक ऑफ जापान (BOJ):

- बैंक ऑफ जापान (बीओजे) जापान का केंद्रीय बैंक है।
- स्थापित: 1882
- मुख्यालय: टोक्यो, जापान
- राज्यपाल: काजुओ उएदा

- BOJ ने अपेक्षाकृत कम ब्याज दरें बनाए रखी हैं, जो अमेरिकी डॉलर की तुलना में येन की कमजोरी में योगदान करती हैं।

विदेशी मुद्रा बाजार (विदेशी मुद्रा):

- विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) बाजार राष्ट्रीय मुद्राओं के व्यापार के लिए वैश्विक बाजार है।

सुविधाएं:

- दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार।

- 24 घंटे संचालित होता है।
- विनिमय दरों को निर्धारित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाता है।
- सीमा पार पूंजी प्रवाह का समर्थन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विनिमय दरें

- आईएमएफ समझौते के लेखों के तहत:
- विनिमय दरें आम तौर पर बाजार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।
- देशों को अनुचित व्यापार लाभ के लिए विनिमय दरों में हेरफेर करने से बचना चाहिए।
- अत्यधिक अस्थिरता या अव्यवस्थित बाजार स्थितियों को संबोधित करने के लिए अस्थायी हस्तक्षेप की अनुमति है।

संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह:

- G7 (सात का समूह)

सदस्य:

- कनाडा
- फ्रांस
- जर्मनी
- इटली
- जापान
- यूनाइटेड किंगडम
- संयुक्त राज्य अमेरिका

- G7 नियमित रूप से वैश्विक वित्तीय स्थिरता और विनिमय दर के मुद्दों पर नीतियों का समन्वय करता है।

- G20 भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों G20 के सदस्य हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

प्लाजा एकाई (1985):

- G5 देशों के बीच समझौता।
- प्लाजा होटल, न्यूयॉर्क में हस्ताक्षरित।
- जापानी येन और जर्मन ड्यूश मार्क के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मूल्यहास करने का इरादा है।
- इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समन्वित मुद्रा हस्तक्षेपों में से एक।

2011 समन्वित हस्तक्षेप:

- ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप और सुनामी के बाद आयोजित।
- G7 देशों ने येन को स्थिर करने के लिए संयुक्त रूप से हस्तक्षेप किया।
- 2026 का हस्तक्षेप तब से पहली समन्वित येन-खरीद कार्रवाई है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| • देश: जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका।  |
| • कार्रवाई: संयुक्त येन-खरीद हस्तक्षेप। |
| • उद्देश्य: जापानी येन को स्थिर करें।   |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| • कारण: अत्यधिक मूल्यहास और बाजार में उतार-चढ़ाव।      |
| • पहली बार 2011 के बाद से।                             |
| • सेंट्रल बैंक: बैंक ऑफ जापान (बीओजे)।                 |
| • संबंधित संस्थान: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)। |
| • संबंधित समूह: G7.                                    |
| • ऐतिहासिक समझौता: प्लाजा समझौता (1985)।               |

सरकार लोकसभा में बैंकर्स बुक साक्ष्य विधेयक, 2026 पेश करेगी



- केंद्र सरकार ने बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, 1891 को बदलने के लिए बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट बिल, 2026 को लोकसभा में पेश करने का प्रस्ताव दिया है, जो न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में बैंक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाला औपनिवेशिक युग का कानून है।
- प्रस्तावित कानून डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देकर, कानून को समकालीन बैंकिंग प्रथाओं के साथ जोड़कर और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के साथ सामंजस्य स्थापित करके कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने का प्रयास करता है, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को बदल दिया है।

नए कानून की आवश्यकता क्यों है?

- मौजूदा बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 को तब अधिनियमित किया गया था जब बैंकिंग लेनदेन मुख्य रूप से भौतिक बहीखातों और रजिस्ट्रों में बनाए रखा गया था। कोर बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड-कीपिंग के तेजी से विस्तार के साथ, सरकार औपनिवेशिक युग के कानून को कानून के साथ बदलना आवश्यक समझती है जो वर्तमान बैंकिंग तकनीक और डिजिटल साक्ष्य आवश्यकताओं को दर्शाता है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य है:

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| • इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को वैध साक्ष्य के रूप में पहचानें।          |
| • अदालतों और जांच एजेंसियों के समक्ष बैंक रिकॉर्ड के उत्पादन को सरल बनाएं। |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| • भौतिक रजिस्ट्रों और कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम करें।             |
| • हार्मोनाइज बैंकिंग एविडेंस लॉज विथ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३।    |
| • वित्तीय लेन-देन से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही में दक्षता में सुधार करना। |

बैंकों की किताबें क्या हैं?

- बैंकों की पुस्तकें ग्राहकों के खातों और बैंकिंग लेनदेन से संबंधित बैंकों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड को संदर्भित करती हैं।

इसमें शामिल है:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| • खाता बहीखाता।                         |
| • कैश बुक।                              |
| • दिन की किताबें।                       |
| • पासबुक।                               |
| • इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन रिकॉर्ड।          |
| • बैंकों द्वारा बनाए गए डिजिटल डेटाबेस। |

- प्रस्तावित कानून के तहत, प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भौतिक रिकॉर्ड के समान कानूनी मान्यता प्राप्त होने की उम्मीद है।

विधेयक का महत्व

कानून से अपेक्षा की जाती है:

- भारत के बढ़ते डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम का समर्थन करना।
- बैंकिंग और वित्तीय विवादों के तेजी से निपटान की सुविधा प्रदान करना।
- वित्तीय अपराधों की जांच में सुधार करें।
- अदालतों में प्रक्रियात्मक देरी को कम करें।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना।



### भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

- द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट, १८७२।

#### प्रमुख विशेषताएँ:

- इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य को वैधानिक मान्यता देता है।
- ईमेल, डिजिटल रिकॉर्ड, एसएमएस, सर्वर लॉग और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को पहचानता है।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को सरल बनाता है।
- डिजिटल गवर्नेंस और ई-कॉमर्स का समर्थन करता है।

#### भारत में डिजिटल बैंकिंग:

- भारत ने इस तरह की पहलों के माध्यम से डिजिटल वित्तीय सेवाओं में तेजी से वृद्धि देखी है:

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई)।
- इंटरनेट बैंकिंग।
- मोबाइल बैंकिंग।
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)।
- डिजिटल रुपया (₹) पायलट।

#### संबंधित कानूनी ढांचा:

### बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:

- भारत में बैंकिंग कंपनियों को विनियमित करता है।
- आरबीआई को बैंकों की निगरानी करने का अधिकार देता है।
- बैंकों के लाइसेंसिंग, प्रबंधन और कामकाज को नियंत्रित करता है।

### सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:

- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई-कॉमर्स के लिए कानूनी आधार बनाता है।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

- विधेयक: बैंकर्स बुक साक्ष्य विधेयक, 2026।
- प्रतिस्थापन: बैंकर्स बुक एक्ट, 1891।
- उद्देश्य: डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता।
- रिलेटेड लॉ: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023.
- संबंधित नियामक: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)।
- सहायक कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।
- क्षेत्र: डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्ष्य।

## भारत के रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने बॉन ओपन डबल्स का खिताब जीता



### रामकुमार रामनाथन:

- भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी।
- एकल और युगल दोनों में विशेषज्ञता।
- डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
- पूर्व एटीपी टूर युगल खिताब विजेता।
- अपनी शक्तिशाली सर्विस और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं।

### विजय सुंदर प्रशांत:

- भारतीय युगल विशेषज्ञ।
- कई एटीपी चैलेंजर खिताबों के विजेता।
- हांगजो ओपन 2024 में अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता।
- भारत की डेविस कप टीम के नियमित सदस्य।

- भारतीय टेनिस जोड़ी रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने जर्मनी के बॉन में बॉन ओपन 2026 एटीपी चैलेंजर युगल खिताब जीता, जो अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर भारतीय टेनिस के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- दोनों ने चैंपियनशिप को सुरक्षित करने के लिए पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट टीम वर्क और निरंतरता का प्रदर्शन किया, जिससे एटीपी चैलेंजर युगल स्पर्धाओं में भारत की उपस्थिति और मजबूत हुई।
- इस जीत से उनकी एटीपी युगल रैंकिंग में सुधार होने की उम्मीद है और आगामी एटीपी टूर टूर्नामेंट और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में उनकी संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

- बॉन ओपन 2026 एकल चैंपियन: जान चोइंस्की (यूनाइटेड किंगडम)

### एटीपी (एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स) के बारे में

- स्थापित: 1972
- मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम

### डेविस कप:

- डेविस कप प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरुष टीम टेनिस चैंपियनशिप है।
- शुरू किया गया: 1900
- भारत तीन बार (1966, 1974 और 1987) डेविस कप के फाइनल में पहुंचा है।

### अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF):

- स्थापित: 1913

- मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम

### परीक्षा फोकस बिंदु:

- टूर्नामेंट: बॉन ओपन 2026।
- श्रेणी: एटीपी चैलेंजर टूर।
- स्थान: बॉन, जर्मनी।
- चैंपियन: रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांता।
- शासी निकाय: एटीपी।
- अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट: डेविस कप।
- वैश्विक शासी निकाय: अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ)।
- महत्व: एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट एटीपी टूर क्वालीफिकेशन के लिए रैंकिंग अंक प्रदान करता है।

## रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC A24) लॉन्च किया



- रक्षा मंत्रालय ने कोलकाता के टीटागढ़ में भारतीय नौसेना की स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पांचवां और अंतिम डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC) DSC A24 लॉन्च किया है। 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल) द्वारा निर्मित, जहाज को पानी के नीचे डाइविंग ऑपरेशन, बचाव सहायता, पानी के नीचे निरीक्षण और तटीय परिचालन समर्थन में नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- डीएससी ए24 को शामिल करना पांच-पोत परियोजना के सफल समापन का प्रतीक है और भारत की स्वदेशी समुद्री क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है।

### DSC A24 के बारे में:

- डीएससी ए24 एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित कटमरैन-हल डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है जिसे तटीय जल और बंदरगाहों में भारतीय नौसेना के पानी के नीचे के मिशनो का समर्थन करने के लिए विकसित किया गया है।

### प्रमुख विशेषताएं:

- डाइविंग समर्थन और पानी के नीचे निरीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया।
- अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों से सुसज्जित।
- बेहतर स्थिरता और समुद्र-कीपिंग के लिए कटमरैन पतवार।
- 380 टन का अनुमानित विस्थापन।
- लंबाई में लगभग 30 मीटर।
- इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) नियमों और विनियमों के तहत निर्मित।

### भूमिकाएँ और क्षमताएँ:

- DSC A24 नौसेना सहायता मिशनो की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करेगा, जिनमें शामिल हैं:
- पानी के नीचे गोताखोरी संचालन।
- जहाजों और उपकरणों के लिए बचाव सहायता।
- पानी के नीचे निरीक्षण और मरम्मत।
- बंदरगाह और तटीय संचालन के लिए समर्थन।
- खोज और बचाव मिशन में सहायता।
- पनडुब्बी से संबंधित गोताखोरी कार्यों के लिए समर्थन।



- इसके शामिल होने से नौसेना की जटिल पानी के नीचे संचालन सुरक्षित और कुशलता से करने की क्षमता बढ़ जाती है।

#### स्वदेशी विकास:

- यह परियोजना भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता को दर्शाती है।

#### महत्वपूर्ण तथ्य

- फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (TRSL) के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
- नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल), विशाखापत्तनम द्वारा आयोजित हाइड्रोडायनामिक विश्लेषण और मॉडल परीक्षण।
- लगभग 70 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री, घरेलू रक्षा विनिर्माण का समर्थन करती है।
- आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है।

#### भारतीय नौसेना के बारे में:

- स्थापना: 26 जनवरी 1950 (रॉयल इंडियन नेवी भारतीय नौसेना बन गई)
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- आदर्श वाक्य: "शाम नो वरुणः" ("महासागरों का स्वामी हमारे लिए शुभ हो")
- प्रमुख: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन
- प्रमुख आदेश:
- पश्चिमी नौसेना कमान – मुंबई।
- पूर्वी नौसेना कमान – विशाखापत्तनम।
- दक्षिणी नौसेना कमान – कोच्चि।

#### नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल)

- संगठन: DRDO
- निर्देशक: डॉ अब्राहम वारुगीस
- स्थान: विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

#### कार्य

- नौसैनिक हथियार प्रणालियों का अनुसंधान और विकास।
- पानी के नीचे की प्रौद्योगिकियां।
- हाइड्रोडायनामिक परीक्षण।
- टारपीडो और सोनार विकास।

#### भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस):

- इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) भारत की प्रमुख जहाज वर्गीकरण सोसायटी है।

- कार्यकारी अध्यक्ष: अरुण शर्मा

- स्थापित: 1975

- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

#### कार्य:

- जहाजों का वर्गीकरण और प्रमाणन।
- समुद्री संरचनाओं का निरीक्षण।
- सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन।
- जहाज निर्माण के लिए तकनीकी मानक।
- संबंधित स्वदेशी नौसेना प्लेटफॉर्म

#### आईएनएस निस्टार:

- भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV)।
- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल), विशाखापत्तनम द्वारा निर्मित।
- गहरे समुद्र में गोताखोरी, पनडुब्बी बचाव और पानी के नीचे बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया गया।
- इसमें 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल है।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

- पोत: डीएससी ए 24।
- प्रकार: डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट।
- बिल्डर: टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल), कोलकाता।
- परियोजना: पांचवां और अंतिम डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट।
- इसके लिए डिजाइन किया गया: गोताखोरी, बचाव, पानी के नीचे निरीक्षण और तटीय संचालन।
- परीक्षण एजेंसी: नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल), विशाखापत्तनम।
- वर्गीकरण: भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस)।
- पहल: मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत।
- संबंधित पोत: आईएनएस निस्टार।

## लेट्स रिवाइज

- ❖ भारत के प्रस्तावित रणनीतिक सीमा रेलवे विस्तार कार्यक्रम की अनुमानित लागत क्या है? ₹45,000 करोड़
- ❖ रणनीतिक रेलवे बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा रसद और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए रेलवे बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है।
- ❖ हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? नशा मुक्त युवा अभियान।
- ❖ नशा मुक्त युवा अभियान का मुख्य लक्ष्य समाज का कौन सा वर्ग है? युवा और छात्र।
- ❖ नशा मुक्ता युवा अभियान किस प्रमुख कार्यक्रम का पूरक है? नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)।
- ❖ एनएपीडीडीआर का पूर्ण रूप क्या है? नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना।
- ❖ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹36,441 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ किस योजना का विस्तार किया गया है? खेलो इंडिया योजना।
- ❖ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों (ANSE) को सहायता के लिए स्वीकृत कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? ₹36,441 करोड़
- ❖ किन दो देशों ने फवरा-यूपीआई क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर लॉन्च किया है? भारत और मालदीव।
- ❖ किस भारतीय संगठन ने फवरा-यूपीआई भुगतान कॉरिडोर शुरू करने में भागीदारी की? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल)।
- ❖ मालदीव के किस संस्थान ने फवरा-यूपीआई भुगतान गलियारे के लिए एनआईपीएल के साथ भागीदारी की? मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए)।
- ❖ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? वर्षा अशोक अगले।
- ❖ किस संगठन ने वर्षा अशोक अगलावे को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)।
- ❖ इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? विली (विलियम) वॉल्श।
- ❖ हाल ही में किन दो देशों ने संयुक्त येन-खरीद हस्तक्षेप किया? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- ❖ किस औपनिवेशिक युग के कानून को बैंकर्स बुक एक्ट बिल, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है? बैंकर्स बुक एक्ट, 1891
- ❖ किस भारतीय जोड़ी ने बॉन ओपन 2026 एटीपी चैलेंजर युगल खिताब जीता? रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांता।
- ❖ किस कंपनी ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC A24) का निर्माण किया है? टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल), कोलकाता।





# *The* **ACHIEVERS** IAS ACADEMY PATNA

## *Daily* **NEWS CHRONICLE**

### IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

### CONTACT US



+91 8434931877



achievers\_ias\_patna



PATLIPUTRA GOLAMBAR



ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC)



achieversiaspatna@gmail.com



Achievers IAS Academy



www.achieversiaspatna.co.in



Achievers IAS Academy, PATNA